RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 27 DECEMBER 2023 TO 2 JANUARY 2024 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 14 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

व्यापारिक समुद्री जहाजों पर कौन कर रहा हमला Page 2

जीएसटी भरने वालों की संख्या में हुआ इजाफा, 5 सालों में 65 प्रतिशत बढ़े टैक्सपेयर्स Page 3

'मेक इन इंडिया' का ठप्पा लगाकर बिक रहे चीनी खिलौने देसी कंपनियों को भारी नुकसान Page 4

editoria!

आत्मनिर्भरता का लक्ष्य

भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं को देखें, तो उनके पीछे आधारभूत दृष्टि देश को हर क्षेत्रको स योजनाओं को देखें तो हर आत्मनिर्भर बनाने है. आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर ही देश संपन्न और समृद्ध बन सकता है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेखांकित किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य देश की समूची आबादी, जिसमें गरीब भी शामिल हैं, को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का है और वे इसी कार्य में समर्पित होकर लगे हुए हैं. उन्होंने यह बात स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की एक बैठक में कही. उल्लेखनीय है कि सड़कों पर खोखा, पटरी, ठेला आदि लगाकर जीवनयापन करने वाले लोग इस योजना के तहत बैंकों से ऋण ले सकते हैं. इस ऋण के लिए उन्हें कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती. स्वनिधि योजना की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस ऋण की गारंटी 'मोदी' है. रेहड़ी-पटरी लगाने वालों के लिए पहले बैंक से ऋण लेना पहाड़ तोड़ने के बराबर था. मजबूरी में उन्हें बाहर से अधिक व्याज पर कर्ज लेना पड़ता था. अब वे आवश्यकतानुसार रकम हासिल कर अपने कारोबार को बेहतर कर सकते हैं. इसी तरह से स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए मुद्रा योजना है. अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 60 करोड़ गरीबों का जीवन स्तर उठाने को लेकर संकल्पित हैं. उनकी इस बात की पुष्टि सरकार की विभिन्न समावेशी नीतियों एवं कार्यक्रमों से होती है. उदाहरण के लिए, जन-धन खातों के जरिये करोड़ों गरीब लोग, खासकर महिलाएं, बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हैं. मोदी सरकार के कार्यकाल में करीब तीन करोड़ लोगों को आवास, चार करोड़ लोगों को बिजली, दस करोड़ लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर, बारह करोड़ लोगों को शौचालय जैसी सुविधाएं मिलने से ये लोग भी देश के विकास से लाभान्वित हो रहे हैं. स्वास्थ्य पर खर्च अच्छी आमदनी वाले परिवारों को भी परेशान कर देता है. गरीब वर्ग के लिए पांच लाख रुपये के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना एक वरदान साबित हुई है. इस बीमा के दायरे में 60 करोड़ लोग आते हैं. कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार ने मुफ्त राशन योजना की शुरुआत की थी. साल 2020 से चल रही इस योजना की अवधि को 2028 तक बढ़ा दिया गया है. राशन योजना से जहां 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषणयुक्त भोजन सुनिश्चित किया जा रहा है, वहीं इससे खुले बाजार में अनाज की कीमतों को नियंत्रित करने में भी मदद मिल रही है.

रुपये का चल गया 'सिक्का'

भारतीय करेंसी में खरीदा जाएगा क्रूड

इकनॉमी और आम आदमी को होगा बड़ा फायदा

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत को ग्लोबल मार्केट में बड़ी सफलता मिल गई है। लंबे समय से जारी कोशिश ने आखिर रंग दिखाना शुरू कर दिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) रुपये में लेनदेन करने वाला पहला देश बन गया है। भारत ने यूएई से कच्चा तेल खरीदकर उसे भारतीय मुद्रा में भुगतान किया है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी के लिए काफी राहत भरी खबर है। इसके साथ ही भारत ने अपनी मुद्रा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की दिशा में भी कदब बढ़ा दिया है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि भारत अन्य तेल आपूर्तिकर्ता देशों के साथ भी इसी तरह के रुपया भुगतान सौदों की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करना एक प्रक्रिया है और इसके लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। फिलहाल हमें एक शुरुआत मिल गई है और यह काफी बेहतर है। हम यूएई से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदते हैं और रुपये में उसे भुगतान करने से बड़ी बचत होगी।

क्यों माना जा रहा बड़ा कदम

गौरतलब है कि अपनी 85 प्रतिशत से अधिक तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत आयात पर निर्भर है। इसके लिए उसे बड़े पैमाने पर डॉलर में भुगतान करना होता है। लेकिन, पिछले साल से भारत ने तेल की खरीद का भुगतान डॉलर के बजाय रुपये में करने की व्यवस्था शुरू की है और इस दिशा में रिजर्व बैंक ने भी जरूरी कदम उठाए हैं। डॉलर में भुगतान करने पर भारत को मुद्रा विनिमय शुल्क यानी फॉरेक्स फीस चुकानी पड़ती है, जिससे यह सौदा काफी महंगा पड़ता है।

कितने रुपये का हुआ भुगतान

इस दिशा में भारत ने जुलाई में यूएई के साथ रुपये में भुगतान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) से 10 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद का भुगतान भारतीय रुपये में किया है. यह हजारों करोड़ रुपये की डील मानी जाती है.

रूस से भी किया था समझौता

इसके अलावा रूस से आयात किए गए कच्चे तेल के कुछ हिस्से का भी भुगतान रुपये में किया गया है. एक अधिकारी ने कहा, 'हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तेल खरीद का भुगतान रुपये में करने से लागत न बढ़े और इसका व्यापार पर किसी भी तरह से नुकसान न पड़े.' 'जहां रकम अधिक नहीं है, वहां रुपये में सौदा निपटान में ज्यादा समस्या नहीं होती है. लेकिन, जब कच्चे तेल का जहाज लाखों डॉलर की कीमत का हो तो समस्याएं होती हैं. भारत व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए स्थिति से निपट रहा है.'

आम आदमी को क्या फायदा

अधिकारी ने कहा कि रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण से डॉलर की मांग कम करने में मदद मिलेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मौद्रिक झटकों का कम असर होगा. इसका फायदा आम आदमी को भी मिलेगा. जब देश का आयात सस्ता पड़ेगा तो यहां बिकने वाली आयातित वस्तुओं की कीमतों में भी कमी आएगी और उनके दाम सस्ते होंगे. अगर भारत कच्चे तेल की खरीद रुपये में करता है तो यह सस्ता पड़ेगा और इसका फायदा आम आदमी को भी होगा.

फेक लोन ऐप्स पर सरकार का कसता शिकंजा

गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए 2500 लोन ऐप

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि गूगल ने अप्रैल 2021 से जुलाई 2022 के बीच अपने प्ले स्टोर से 2,500 से अधिक धोखाधड़ी वाले लोन ऐप को सस्पेंड किया है या हटा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि सरकार धोखाधड़ी वाले लोन ऐप को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई और अन्य रेगुलेटर संबंधित अथॉरिटी के साथ लगातार काम कर रही है।

एक प्रश्न के लिखित जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार धोखाधड़ी करने वाले फेक लोन ऐप पर निगरानी बनाए हुए है। इन लोन ऐप को नियंत्रित करने के लिए सरकार आरबीआई और अन्य नियामकों सहित संबंधित हितधारकों के साथ लगातार काम कर रही है। अंतर-नियामक मंच, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठकों में भी धोखाधड़ी करने वाले इन ऐप्स को लेकर नियमित चर्चा होती है, ताकि इनपर नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि गूगल ने प्ले स्टोर पर लोन देने वाले ऐप को शामिल करने के संबंध में अपनी पॉलिसी को अपडेट किया है।

नई पॉलिसी के बाद गूगल ने प्ले स्टोर पर केवल उन्हीं ऐप को रखा है जो विनियमित संस्थाओं की ओर से जारी किए गए हैं। या फिर जो विनियमित संस्थाओं के साथ साझेदारी में काम कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अप्रैल 2021 और जुलाई 2022 के बीच गूगल ने लगभग 3500 से 4,000 लोन देने वाले ऐप की समीक्षा की है। जिसके बाद गूगल प्ले स्टोर ने अपने प्लेटफॉर्म से 2500 से अधिक धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप को अपने प्ले स्टोर से निलंबित कर दिया है।

व्यापारिक समुद्री जहाजों पर कौन कर रहा हमला

नौसेना ने उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय नौसेना ने व्यापारिक जहाज एमवी केम प्लूटो पर हमले अरब सागर में समुद्री सुरक्षा अभियान शुरू किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद नौसेना ने समुद्री सुरक्षा अभियान की जानकारी दी। इससे पहले राजनाथ सिंह ने कहा था कि जिस किसी ने भी इन हमलों को अंजाम दिया है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, भले ही वे समुद्र तल में छिपे हों।

अरब सागर में चार नवीनतम युद्धपोत तैनात

नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार ने कहा कि भारत ने व्यापारी जहाजों पर समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए कई तरह की तैयारी की है। चार नवीनतम युद्धपोतों को तैनात किया गया है। इनके अलावा पीआई विमान, डोर्नियर्स, सी-गार्डियन, हेलीकाप्टर और भारतीय तट रक्षक जहाज भी इन खतरों का मुकाबला करने में शामिल हो रहे हैं।

समुद्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा

नौसेना प्रमुख ने कहा कि समुद्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के साथ समन्वय में कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि व्यापारिक जहाज एमवी केम प्लूटो पर 25 दिसंबर को मुंबई पहुंचा है। वह समुद्र में एंकर डाल कर खड़ा है। इसमें 21 भारतीय और एक वियतनामी क्रू सदस्य मौजूद हैं।

ड्रोन या मिसाइल के हमले जैसा

भारतीय नौसेना की ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम ने आरंभिक जांच में बताया कि यह किसी छोटे ड्रोन से किया गया हमला नहीं है। यह किसी बड़े ड्रोन या मिसाइल के हमले जैसा है। अरब सागर में व्यापारिक जहाज पर ड्रोन हमले की जांच हो रही है।

कई तरह की एजेंसियां कर रही जांच

ड्रोन के टुकड़े और जहाज के टुकड़ों की जांच हो रही है। इस मामले में कई एजेंसियां काम कर रही हैं। इसमें नौसेना की एक्सप्लोसिव आर्डिनेंस टीम को भी जोड़ा गया है। अभी इस हमले को लेकर कई तरह की एजेंसियां जांच करने वाली हैं। बाद में इसका सामान दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया जाएगा।

जापान के सबसे बड़े बैंक ने भी माना भारत का लोहा

चीन से हुआ मोह भंग

नई दिल्ली। एजेंसी

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी वाले देश चीन को हाल में कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे दुनिया की कई कंपनियों का चीन से मोह भंग होने लगा है। इनमें जापान के सबसे बड़े बैंक मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप इंक (श्ळइउ) का नाम भी शामिल हो गया है। इस बैंक ने अब भारत में अपना निवेश बढ़ाने का फैसला किया है। इस फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ के सात परसेंट रहने का अनुमान है जो बड़े देशों में सबसे ज्यादा है। भारत कैपिटल मार्केट्स के लिए ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। यही वजह है कि दुनियाभर की प्राइवेट इक्विटी कंपनियां और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भारत का रुख कर रहे हैं।

एमयूएफजी के सीईओ हीरोनोरी कामेजावा ने कहा कि भारत के लिए इकनॉमिक ग्रोथ कोई चुनौती नहीं है। यह होना ही है। जापान के इस सबसे बड़े बैंक ने हाल के वर्षों में भारत में अपना निवेश बढ़ाया है। पिछले साल अगस्त में बैंक ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी में अपनी ब्रांच खोली थी। साथ ही बैंक ने स्टार्टअप कंपनियों के लिए एक फंड स्थापित किया है। इसी महीने उसने एक भारतीय फिनटेक कंपनी डीएमआई फाइनेंश प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदी है।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कामेजावा ने कहा कि हम भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा भारत बैंक के बैक ऑफिस ऑपरेशंस सेंटर का काम करता है। चीन की तुलना में भारत में ज्यादा संभावनाएं है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर भारत ऐसे निवेश को आकर्षित कर सकता है जो चीन से बचना चाहता है।'

10 करोड़ जनधन अकाउंट हो गए बंद!

खातों में जमा 12 हजार करोड़ रुपये लेने वाला कोई नहीं

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार की ओर से आम लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए शुरू की गई जनधन योजना (PM Jan Dhan Yojana) में अब तक 51 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खुले हैं। इनमें से 10 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट डीएक्टिव हो चुके हैं। इन बंद हुए बैंक अकाउंट में करीब 12 हजार करोड़ रुपये जमा हैं। इन रुपयों को लेने वाला कोई नहीं है। वित्त मंत्रालय की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। इस योजना के जरिए गांव के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ा गया है। इस योजना ने गरीबों को सरकारी योजना में फायदा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है।

जनधन खातों ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की सफलता में बड़ा योगदान दिया था। मोदी सरकार की जनधन योजना (PM Jan Dhan Yojana) काफी लोकप्रिय है। गरीबों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ देने के लिए साल 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत कई खास तरह की सुविधाएं मिलती हैं। कोई भी गरीब इसमें अपना खाता खुलवा सकता है।

क्यों बंद हुए 10 करोड़ जनधन अकाउंट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बंद हुए 10 करोड़ जनधन अकाउंट में 12,779 करोड़ रुपये जमा हैं। इन बंद खातों में 4.93 करोड़ अकाउंट महिलाओं के हैं। जानकारी के मुताबिक, देश में करीब 51.11 करोड़ पीएम जनधन खाते हैं। इन खातों के बंद होने के कई कारण हैं। इसका अकाउंट होल्डर्स से कोई सीधा संबंध नहं है। कई महीनों से खातों में ट्रांजेक्शन नहीं करने के कारण भी खाते बंद हुए हैं। आरबीआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक, अगर खाते में दो साल से ज्यादा समय तक कस्टमर कोई लेनदेन नहीं करता है तो बचत और चालू खाते को निष्क्रिय माना जाता है। बैंक इन निष्क्रिय खातों के प्रतिशत को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जनधन खातों में न्यूनतम राशि रखने की जरूरत नहीं पड़ती है।

AIF के रास्ते गड़बड़ियों रोकने के लिए RBI के उठाया सख्त कदम, सर्कुलर जारी

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) के जरिये पुराने लोन को लौटाने के लिए नया कर्ज लेने की व्यवस्था (एवरग्रिनिंग) पर लगाम लगाने को लेकर कदम उठाया है। इसके तहत बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनैंशल कंपनियां उस AIFs की किसी भी योजना में निवेश नहीं कर सकतीं, जिसने वित्तीय संस्थान से पिछले 12 महीनों में कर्ज लेने वाले लैंडर्स की कंपनी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से निवेश कर रखा है। बैंक और एनबीएफसी अपने नियमित निवेश गतिविधियों के तहत AIF की इकाइयों में निवेश करती हैं। वेंचर कैपिटल फंड, इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, एंजल फंड समेत अन्य AIF के तहत आते हैं। आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा कि बैंक और एनबीएफसी के कुछ लेन-देन में AIF शामिल है। इससे रेगुलेटरी लेवल पर चिंता सामने आई है। रिजर्व बैंक ने कहा कि इसके माध्यम से AIF के जरिये पुराने कर्ज को लौटाने के लिए नई कर्ज की व्यवस्था पर रोक लगाने के लिए कदम उठाये हैं। साथ ही आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों से कहा है कि ऐसे निवेश को 30 दिन के भीतर निपटाने की जरूरत होगी। RBI ने कहा कि यदि रेग्यूलेटेड एंटिटि (REs) , जैसे बैंक और एनबीएफसी ऐसा करने में असमर्थ है, तो उन्हें इन निवेशों पर 100 प्रतिशत प्रावधान करने की आवश्यकता होगी।

जनसम्पर्क आयुक्त श्री पोरवाल ने पदभार ग्रहण किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

सचिव जनसम्पर्क श्री विवेक पोरवाल ने आज जनसम्पर्क आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने जनसम्पर्क संचालनालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों की बैठक ली। जनसम्पर्क आयुक्त श्री पोरवाल ने जनसम्पर्क की कार्यप्रणाली की वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करते हुए बेहतर तरीके से कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने विभाग के विभिन्न प्रभागों में किये जा रहे कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने म.प्र. माध्यम में भी प्रबंध संचालक (एम.डी.) का पदभार ग्रहण किया।

जीएसटी भरने वालों की संख्या में हुआ इजाफा, 5 सालों में 65 प्रतिशत बढ़े टैक्सपेयर्स

आंकड़ा 1.13 करोड़ रुपये पर पहुंचा

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश में टैक्स पेयर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। टैक्सपेयर्स की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जीएसटी कलेक्शन में लगातार इजाफा हो रहा है। अप्रैल, 2023 तक बीते पांच सालों में जीएसटी रिटर्न में बड़ी तेजी देखने को मिली है और टैक्सपोयर्स की संख्या में 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह संख्या बढ़कर 1.13 करोड़ हो गई।

करदाताओं के अनुपालन में सुधार के कारण अप्रैल, 2023 तक पांच वर्षों में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या लगभग 65 प्रतिशत बढ़कर 1.13 करोड़ हो गई। वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत सक्रिय करदाताओं की संख्या बढ़कर 1.40 करोड़ हो गई जो अप्रैल 2018 में 1.06 करोड़ थी। मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में फाइलिंग माह के अंत तक 90 प्रतिशत पात्र करदाता जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। यह आंकड़ा जीएसटी लागू होने के पहले वर्ष 2017-18 में 68 प्रतिशत था।

मंत्रालय ने सोशल नेटवर्किंग मंच एक्स पर पोस्ट किया, 'जीएसटी नियमों और प्रक्रियाओं में सरलीकरण के परिणामस्वरूप पात्र करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने का प्रतिशत बढ़ गया है।' एक जुलाई, 2017 को राष्ट्रव्यापी जीएसटी लागू किया गया था। इसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे एक दर्जन से अधिक स्थानीय करों को शामिल किया गया था।

जीएसटीआर-3बी दाखिल करने वालों की संख्या अप्रैल, 2018 में 72.49 लाख से बढ़कर अप्रैल, 2023 तक 1.13 करोड़ हो गई। जीएसटीआर-3बी बाहरी आपूर्ति विवरण और कर भुगतान दाखिल करने के लिए मासिक रिटर्न फॉर्म है। मंत्रालय ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा, 'जीएसटी में प्रभावी नीति और प्रणालीगत बदलावों के कारण पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में अनुपालन स्तर में सुधार हुआ है।' मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में रिटर्न फाइलिंग में वृद्धि अनुपालन स्तर में सुधार का संकेत देती है। नवंबर में मासिक जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष में यह छठी बार है कि मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया था।

रिकॉर्ड ऊंचाई पर Sensex-Nifty

चार दिन में निवेशकों ने कमाए रुपए 11 लाख करोड़

मुंबई। एजेंसी

स्टॉक मार्केट में बुधवार को लगातार चौथे दिन खरीदारी का रुझान रहा और घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) और निफ्टी 50 (Nifty 50) रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। बाजार की तेजी में चार दिन में निवेशकों की पूंजी 11.11 लाख करोड़ रुपये बढ़ी है। आज सेंसेक्स पहली बार 72 हजार और निफ्टी पहली बार 21600 के पार पहुंचकर बंद हुआ है।

स्टॉक मार्केट में लगातार चौथे दिन खरीदारी का रुझान रहा और घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) और निफ्टी 50 (Nifty 50) रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। बाजार की तेजी में निवेशकों ने आज 2.39 लाख करोड़ रुपये कमा लिए। वहीं चार दिन में निवेशकों की पूंजी 11.11 लाख करोड़ रुपये बढ़ी है। अब इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सों की बात करें तो सेंसेक्स आज 0.98 फीसदी की बढ़त के साथ 72038.43 और निफ्टी 1 फीसदी की मजबूती के साथ 21654.75 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स पहली बार 72 हजार और निफ्टी पहली बार 21600 के पार पहुंचकर बंद हुआ है।

मार्केट को लगभग हर सेक्टर के शेयरों से सपोर्ट मिला। HDFC Bank के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती की नियुक्ति को फिर से मंजूरी मिली है जिसके चलते इसके शेयर 1% से अधिक उछल गए। हैवीवेट शेयर होने के चलते इंडेक्सों को इससे सपोर्ट मिला। आज निफ्टी के मीडिया और ऑयल एंड गैस को छोड़ सभी सेक्टर के इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि इनमें भी गिरावट आधे फीसदी से कम ही रही। निफ्टी बैंक आज 1.20 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ है।

31 दिसंबर से पहले हर हाल में निपटा लें ये 5 जरूरी काम

नई दिल्ली। एजेंसी

दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है। कुछ ही दिन बाद नए साल 2024 की शुरुआत हो जाएगी। नया साल कई बदलावों को लेकर आने वाला है। ऐसे में बहुत से काम हैं जो आपको 31 दिसंबर तक हर हाल में निपटाने जरूरी हैं। ऐसा नहीं करने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन बदलावों के बारे में आपको पहले से जानकारी होना जरूरी है। आज हम आपको इन्हीं कामों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको इसी महीने यानी दिसंबर में निपटाना जरूरी है। इसमें आयकर रिटर्न से लेकर म्यूचुअल फंड के नोमिनेशन से जुड़े नियम शामिल है। अगर आपने डेडलाइन से पहले ये 5काम नहीं किये तो किन नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है।

1 - लॉकर एग्रीमेंट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक, बैंकों में लॉकर (Bank Locker) रखने वाले ग्राहकों को संशोधित लॉकर एग्रीमेंट्स जमा कराने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया है। बैंक जाकर ग्राहकों को अपडेटेड एग्रीमेंट जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको लॉकर खाली करना पड़ सकता है। आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि इस साल की समाप्ति तक सौ फीसदी ग्राहकों के अपडेटेड एग्रीमेंट जमा हो जाने चाहिए।

2- इनकम टैक्स रिटर्न

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ विलंबित आयकर रिटर्न (ITR) भरने करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2023 है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न भरना सबसे जरूरी काम है। आयकर अधिनियम की धारा 234 इ के तहत, जो व्यक्ति तय तारीख से पहले रिटर्न दाखिल नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं देर से आईटीआर भरने वालों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि, जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें अभी 1000 रुपये का ही जुर्माना देना होगा, लेकिन 31 दिसंबर के बाद उन्हें भी पांच हजार रुपये जुर्माने के रूप में चुकाने होंगे।

3- यूपीआई आईडी हो जाएगी बंद

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप के यूपीआई को बंद करने का फैसला किया है। जिन यूपीआई आईडी का इस्तेमाल पिछले एक साल से नहीं किया गया है। वह बंद हो जाएंगे। ऐसे में अगर आपका भी कोई ऐसा यूपीआई आईडी है तो उसे तुरंत ट्रांजेक्शन कर लेना चाहिए।

4- एसबीआई की स्कीम हो जाएगी बंद

भारतीय स्टेट बैंक की अमृत कलश फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम (SBI Amrit Kalash Scheme) भी 31 दिसंबर 2023 को बंद हो रही है। इसमें निवेश करने का आपके पास अंतिम मौका है। इस योजना में बैंक 7.50 फीसदी तक का ब्याज दे रहा है। इसमें प्रीमैच्योर और लोन दोनों की सुविधा मिलती है।

5 डीमैट अकाउंट

सेबी ने सभी डीमैट खाताधारकों के लिए 1 जनवरी, 2024 तक नॉमिनी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। खाताधारकों के विफल रहने पर वे शेयरों में लेनदेन नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने की समय सीमा पहले 30 सितंबर थी, जिसे तीन महीने बढ़ा दिया गया था।

'मेक इन इंडिया' का ठप्पा लगाकर बिक रहे चीनी खिलौने

देसी कंपनियों को भारी नुकसान

नई दिल्ली। एजेंसी

खिलौनों की क्वालिटी सुधारने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने कड़े नियम बनाए हैं। इन नियमों का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। सरकार की कोशिशों के बावजूद टॉयज के इंपोर्ट में कमी नहीं आ रही है। इससे देसी निर्माताओं को नुकसान हो रहा है। खिलौना निर्माता सरबजीत सिंह ने बताया कि BIS ने मैन्युफैक्चरर्स के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया आसान की है। रिन्युअल फीस में भी रियायत दी जाती है। माइक्रो इंडस्ट्रीज को कई तरह की छूट मिलती है। इन सबके बावजूद निर्माताओं का माल उम्मीद के मुताबिक नहीं बिक रहा है। दरअसल, अलग-अलग तरह से विदेशी खिलौने इंपोर्ट हो रहे हैं। उससे नुकसान झेलना पड़ रहा है। BIS का नियम 14 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलौनों पर लागू होता है। ऐसे में एक्सपोर्टर अपने टॉयज पर शो करते हैं कि वो 14 साल के अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। फिर ये BIS नॉर्म्स से बाहर हो जाते हैं। ये टॉयज आसानी से इंपोर्ट हो जाते हैं।

चीन से खिलौनों के कई पार्ट्स अलग-अलग पोर्ट से भारत में आ रहे हैं। यहां पेचकस से कसकर 'मेक इन इंडिया' डब्बों में पैककर बेचते हैं जबकि भारत में खिलौना नहीं बना है। सरबजीत ने बताया कि BIS लागू होने से पहले 85 प्रतिशत खिलौने बाहर से आते थे। तमाम प्रयासों के बावजूद इंपोर्ट में ज्यादा कमी नहीं ला सके हैं। आज भी 50 से 60 प्रतिशत खिलौने विदेश से आते हैं। कुछ टॉयज मिस डिक्लियरेंस करके लाए जा रहे हैं। इनमें खिलौने का नाम नहीं होता है। उसमें गिफ्ट और डेकोरेटिव आइटम शो करते हैं। इससे इंपोर्ट ड्यूटी और BIS से भी बच जाते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा।

दुकान पर खिलौना देखकर पसंद करते हैं बच्चे

द टॉयज असोसिएशन ऑफ इंडिया के चीफ कॉर्डिनेटर अमिताभ खरबंदा ने कहा कि BIS ने तय कर रखा है कि एक पार्टिकुलर खिलौना 3 साल या 5 साल से ऊपर का बच्चा ही खेल सकता है। मगर, इंपोर्टेड खिलौनों पर लिखा होगा कि उसे 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे खेल सकते हैं, तो यह नियमों का सरासर उल्लंघन है। कोई भी निर्माता 10 तरह के खिलौने बनाता है। यदि सभी पर लिखे कि 14 साल से बड़े बच्चे खेलेंगे, तो किसी को लैब लगाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे दुकान में खिलौना देखकर पसंद करते हैं। कोई ग्रेडिंग पर ध्यान नहीं देता। इस तरह की समस्याओं पर सरकार को गौर करना चाहिए। कोशिश हो कि देसी निर्माताओं का प्रोडक्शन और बिजनेस दोनों बढ़े।

अपेक्षा के अनुरूप नहीं इंडस्ट्री का ग्रोथ

द टॉयज असोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेजिडेंट अजय अग्रवाल ने कहा कि इंपोर्टेड टॉयज पर ''घ्ए के नियम लागू नहीं हो पा रहे हैं। काफी मात्रा में खुला माल विदेश से आ रहा है। BIS को गहन विचार करना होगा। मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। नियम ऐसे हों, जिससे लोकल निर्माताओं को काम मिले। अभी पॉलिसी में क्लियरिटी नहीं है। खिलौनों के पार्ट्स के साथ तैयार टॉयज भी विदेश से आ रहे हैं। दिल्ली और देश के दूसरे बाजार विदेशी खिलौनों से भरे हैं। सरकार भारतीय खिलौना निर्माताओं और व्यापारियों को आगे बढ़ाना चाहती है। फिर भी इंडस्ट्री ग्रोथ अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। देश में बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स के पास लाइसेंस है। अधिक से अधिक लोगों को लाइसेंस दिए जाएं। व्यापारियों और निर्माताओं के संग इंटरेक्शन होगा, तो अधिक लोग खिलौना उद्योग से जुड़ेंगे। BIS के संदर्भ में इंपोर्ट पॉलिसी के मापदंड स्पष्ट होने चाहिए।

खिलौनों पर जनवरी 2021 से BIS मानक अनिवार्य

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाला BIS मानक तय करने वाला राष्ट्रीय निकाय है। जनवरी 2021 से खिलौने के लिए गुणवत्ता प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। किसी भी व्यापारी को ऐसे खिलौनों का निर्माण, आयात, बिक्री या वितरण, भंडारण या बिक्री के लिए प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, जो भारतीय मानक के अनुरूप नहीं हैं। BIS ने जुलाई 2022 में लोगों से ISI के निशान वाले खिलौने खरीदने का आग्रह किया था। इससे टॉयज की क्वालिटी का प्रमाणन सुनिश्चित होता है। उपभोक्ताओं को यदि पता चलता है कि खिलौने बिना घ्ए के निशान के बेचे जा रहे हैं, तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। BIS केयर मोबाइल ऐप पर कंप्लीट दर्ज हो सकती है।

अब हाईवे पर GPS सेटेलाइट के जरिए होगा टोल कलेक्शन

नई दिल्ली। एजेंसी

देशभर में हाईवेज पर जल्द ही कोई टोल प्लाजा दिखाई नहीं देगा। इससे लोगों को हाईवे पर जाम से मुक्ति मिलेगी। सरकार अब जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम लाने जा रही है। इसकी जल्द ही शुरुआत हो जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि राजमार्ग टोल प्लाजा की मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार अगले साल मार्च तक जीपीएस-आधारित टोल संग्रह प्रणाली सहित नई प्रौद्योगिकियां पेश करेगी। इस कदम का उद्देश्य राजमार्गों पर यातायात को कम करना और राजमार्गों पर यात्रा की गई सटीक दूरी के लिए वाहन चालकों से शुल्क वसूलना है।

सरकार कर रही तैयारी

गडकरी ने कहा, ''सरकार देश में टोल प्लाजा व्यवस्था को बदलने के लिए जीपीएस-आधारित टोल सिस्टम सहित नई प्रौद्योगिकियां लाने पर विचार कर रही है। हम अगले साल मार्च तक देश भर में नए जीपीएस उपग्रह-आधारित टोल संग्रह शुरू कर देंगे।'' गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों को रोके बिना स्वचालित टोल संग्रह को सक्षम बनाने के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली की दो प्रायोगिक परियोजनाएं भी चलाई है। वर्ष 2018-19 के दौरान टोल प्लाजा पर वाहनों को औसतन आठ मिनट का इंतजार करना पड़ता था। वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में फास्टैग व्यवस्था लागू होने से यह समय घटकर महज 47 सेकंड हो चुका है।

प्रतीक्षा समय में हुआ सुधार

कुछ स्थानों पर खासकर शहरों के पास घनी आबादी वाले कस्बों में टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा के समय में काफी सुधार हुआ है, फिर भी अत्यधिक भीड़ के समय यह समय बढ़ जाता है। इस बीच, गडकरी ने कहा कि सरकार आम चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले 1,000 किलोमीटर से कम लंबाई की राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 'बनाओ-चलाओ और सौंप दो' (बीओटी) मॉडल पर 1.5-2 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की बोली मंगाएगी। आम चुनाव अप्रैल-मई 2024 में होने की संभावना है।

उत्पादकता वृद्धि, आय असमानता और औद्योगिक सघनीकरण पर कृत्रिम बुद्धिमता के प्रभाव

राजकुमार जैन
स्वतंत्र लेखक एवं विचारक

वैश्विक परिदृश्य में कृत्रिम बुद्धिमता का चौतरफा विकास हो रहा है और समाज को लचीला होकर उसके साथ लयबद्ध होना पड़ेगा। एआई स्वयं रचनात्मकता और वैज्ञानिक खोज के बूते पर समाज को न केवल ज्ञात चीजों को बेहतर करने में मदद करता है बल्कि कल्पनातीत चीजों को भी वास्तविकता में करने में सक्षम बनाता है। कृत्रिम बुद्धिमता का भविष्य पूर्व नियोजित ना होकर कई चीजों का मिलाजुला परिणाम होगा, जिसमें आज लिये गये तकनीकी और नीतिगत निर्णय भी शामिल होंगें। एआई के साथ मानवता के हित में बेहतर भविष्य तलाशने के लिए बेहतर नीतियों की आवश्यकता होगी।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी अभिनव तकनीकी क्रांति के वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले समग्र प्रभाव को समझने के लिए तीन क्षेत्रों का अध्ययन करना आवश्यक है, उत्पादकता, प्रति व्यक्ति आय, और औद्योगिक फैलाव।

उत्पादकता वृद्धि : राष्ट्रों की समृद्धी, खुशहाली और उनके नागरीकों के जीवन स्तर को दर्शाने वाला आर्थिक विकास काफी हद तक उत्पादकता वृद्धि पर निर्भर करता है। उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देना दुनिया के समस्त देशों के लिए बुनियादी आर्थिक चुनौती है। उच्च उत्पादकता के साथ, बजट घाटे, गरीबी, स्वास्थ्य-देखभाल और पर्यावरण जैसी जटिल समस्याओं का प्रबंधन करना सुविधाजनक हो जाता है।

अभिनव प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग से श्रमबलों का कुशल समय प्रबंधन अधिक दक्षता से करना संभव हो सकेगा जो श्रम उत्पादकता में आशातीत वृद्धि की नीव रखेगा। एआई को श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के एक बड़े हिस्से पर लागू कर उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। कामगारों को नौकरी से हटाने के बजाय एआई मानव संसाधनों की एक बड़ी संख्या को गैर-नियमित, रचनात्मक और आविष्कारशील कार्यों पर अधिक समय बिताने के लिए मुक्त करेगा, जिसके परिणामस्वरूप, पहले से उपलब्ध मानव संसाधन नवीन समस्याओं के निपटान पर वांछित समय व्यतीत कर पाएंगे। इसके नतीजे में अर्थव्यवस्था न केवल उत्पादकता के उच्च स्तर पर पहुँचती है, बल्कि स्थायी रूप से उच्च विकास दर भी हासिल की जा सकती है।

आय असमानता : बीते कुछ दशकों से आय असमानता में वृद्धि वैश्विक स्तर पर नीती नियोजकों के लिये एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न अवतारों ने मध्यम-आय वाली नियमित नौकरियों को स्वचालित करके श्रम बल को उच्च-आय और निम्न-आय वाले कामगारों में ध्रुवीकृत कर आय असमानता में बड़ा योगदान दिया है। लेकिन संतोषप्रद बात यह है कि यह बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की आहट नहीं है। इसके उलट कार्यबल पर एआई का मुख्य प्रभाव कम अनुभवी या कम जानकार कर्मचारीयों को उनकी नौकरियों में बेहतर बनाने में मदद करना है। उदाहरण के लिए, अनुभवहीन सॉफ्टवेयर कोडर अब 'कोपायलट' जैसे एआई मॉडल की सहायता से बेहतर परिणाम दे पा रहे हैं। कोपायलट का उपयोग करके एक नौसखिया भी एक उस्ताद कोडर की बराबरी कर लेता है।

कॉल सेंटर में उपभोक्ता सहायता जैसा जटिल कार्य करने वाले एजेंटों के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन एजेंटों के साथ एआई सहायक को लगाया गया था, उनमें से सबसे कम कुशल या प्रशिक्षु एजेंटों ने सबसे अधिक उत्पादक प्रदर्शन किया । यदि नियोक्ता एआई के इन लाभों को अपने कार्यबल के साथ साझा करते हैं, तो आय का वितरण बराबरी से समतुल्य बनाने में सहूलियत होगी।

बेहतर आय-समानता का सुखद माहौल बनाने के अलावा, संस्थानों में एआई का उपयोग श्रमबलों की वास्तविक अर्थों में जमीनी मदद भी कर सकता है। कार्यस्थल पर नियमित और सूत्रबद्ध किस्म के कार्यों के एक बेहतरीन विकल्प के रूप में उबाऊ, श्रमसाध्य और थकाऊ काम मानव हाथों से अपने हाथों में लेकर, एआई काम के बुनियादी मनोवैज्ञानिक अनुभव में दिलचस्प सुधार ला सकता है। दरअसल, कॉल सेंटर अध्ययन में पाया गया कि एजेंटों को एआई सहायक का साथ मिलने से न केवल उनकी उत्पादकता बढ़ी बल्कि नौकरी छोड़ने वालों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आई जिससे ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि हुई।

औद्योगिक सघनता : 1980 के दशक की शुरुआत से ही कई अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक सघनता, जो एक क्षेत्र की सबसे बड़ी कम्पनीयों की सामूहिक बाजार हिस्सेदारी मापने का पैमाना है- में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। पूंजी-प्रधान कम्पनीयां अपने छोटे प्रतिद्वंदीयों की तुलना में उत्कृष्ठ लेकिन महंगे तकनीकी ज्ञान तक गहरी पहुंच रखती हैं जो औद्योगिक सघनता बढ़ाने के लिए बड़ी हद तक जिम्मेदार है। औद्योगिक सघनता बढ़ जाने से केवल बड़ी कंपनियां ही अपने मुख्य व्यवसाय में आवश्यक एआई टूल्स का गहन उपयोग कर पाती हैं। एआई इन फर्मों को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक उत्पादक, लाभदायक और बड़ा बनने में सहायता करता है।

जीपीटी-4 मॉडल को इसके प्रारंभिक विकास के दौरान प्रशिक्षित करने के लिए ₹100 मिलियन से अधिक की लागत आई और इसे चलाने के लिए प्रति दिन लगभग ₹ 700,000 की आवश्यकता होती है। एआई के विकास और परिचालन में उच्च कम्प्यूटेशनल क्षमता की दिनोंदिन बढ़ती मांग के चलते सटीक और लाभदायक एआई मॉडल विकसित करना और भी महंगा होता जा रहा है। एक विशिष्ट और वृहद एआई मॉडल को विकसित करने की लागत अरबों डॉलर तक पहुँच सकती है जिसको वहन करने हेतु आवश्यक आर्थिक संसाधन केवल बड़ी कम्पनीयों के पास ही होते हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर डेटासेट प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरी करने के लिए बड़ी कम्पनीयों के पास पहले से ही अपने ग्राहकों की लंबी चौड़ी लिस्ट उपलब्ध है जो नई और छोटी स्टार्टअप कम्पनीयों के पास नहीं होती है। यह भी हो सकता है कि केवल सबसे बड़ी कम्पनीया और उनके व्यावसायिक भागीदार ही विशिष्ट रूप से चिन्हित एआई विकसित करें, जैसा कि अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई जैसी फर्मों ने किया है।

लेकिन हालात इतने बुरे ना बनें और नवीनतम तकनीक सबको सुलभ हो इसलिए निम्न-औद्योगिक-सघनता के पैरोकार, ओपन-सोर्स एआई मॉडल (जैसे मेटा के लामा या बर्कले के कोआला) को व्यापक रूप से उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रयासरत हैं। दूसरी तरफ छोटे व्यवसायों को उद्योग-अग्रणी उत्पादन प्रौद्योगिकियों तक पहुंच उपलब्ध करवाने के लिए गैर-लाभकारी संस्थाओं, शिक्षाविदों और व्यक्तिगत कोडर्स का जमवाड़ा, एक ऐसा ओपन-सोर्स एआई पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है जो विकसित एआई मॉडल तक व्यापक पहुंच को सुगम बना रहा है। बड़ी संख्या में एकाधिकार के विरोधी लोगों के स्वप्रेरित जुड़ाव से ओपन सोर्स मॉडल को कम खर्च में प्रशिक्षित किया जा सकता है। एक शोधकर्ता के विचार में, व्यापक समर्थन के चलते ओपन सोर्स मॉडल महंगे मालिकाना हक वाले निजी मॉडल से कहीं आगे निकल सकते हैं।

यदि नीति निर्माता यह स्वीकारते हैं कि वैश्विक आर्थिक विकास के लिए एआई को विभिन्न दिशाओं में विकसित करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाना चाहिए, तो कुछ नीतिगत प्रश्नों के ईमानदार जवाब अनिवार्य रूप से खोजने होंगे। नीतियां एआई के उन प्रकारों को कैसे प्रोत्साहित कर सकती हैं जो मानव श्रम की नकल करने और उसे प्रतिस्थापित करने के बजाय उनके पूरक होंगे। कौनसे विकल्प ऐसे एआई के विकास को प्रोत्साहित करेंगे, जिसका उपयोग केवल सबसे बड़ी कंपनियों के बजाय सभी आकार प्रकार की कंपनियां कर सकती हैं। इसके लिए किस प्रकार के ओपन-सोर्स पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होगी, और नीति निर्माता इसका समर्थन कैसे करेंगे। एआई प्रयोगशालाओं को मॉडल विकास के लिए, और कंपनियों को एआई कार्यान्वयन के लिए कैसे दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसके साथ ही श्रमिक संघों को भी यह सोचना होगा कि वे एआई के साथ किस तरह का संबंध चाहते हैं और एआई युक्त भविष्य में उनकी मांगें क्या होंगी।

एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए एआई अग्रणी बड़े व्यावसायिक घरानों को इस बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा कि वे अपने कार्यबल के साथ एआई को कैसे एकीकृत करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया पर संघीय विधायिका और नियामकों का भी व्यापक प्रभाव होगा जो यह निश्चित करेंगे कि मौजूदा वस्तुओं, सेवाओं और प्रणालियों में मामूली बदलावों के बजाय, समाज को ऐसा एआई कैसे हासिल होगा, जो क्रांतिकारी नवाचार को बढ़ावा देता है। समाज पर एआई के आर्थिक प्रभावों का आकलन खरबों डॉलर में होने की संभावना है, तो एआई के अर्थशास्त्र पर शोध में कहीं अधिक निवेश किया जाना चाहिए। अनुसंधान प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित करने और एक स्मार्ट नीति एजेंडा विकसित करने से समाज को एआई के साथ निरंतर और समावेशी आर्थिक विकास के भविष्य की ओर बढ़ने में मदद मिल सकती है।

सस्ती दाल और सस्ते आटे के बाद अब सस्ते चावल भी बेचेगी सरकार, दाम होगा

नई दिल्ली। एजेंसी

इस समय चावल-दाल की कीमत कुछ ज्यादा ही है। इससे आम आदमी परेशान नहीं हो, इसके लिए सरकार ने कई कदम उठा लिए हैं या उठाने की घोषणा की है। पहले तो सरकार ने देश के करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की योजना को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया। अब भारत ब्रांड के तहत सस्ते चावल बेचने की तैयारी है। इससे पहले सरकार भारत ब्रांड (Bharat Brand) के तहत सस्ती दाल (Bharat Dal) और सस्ते आटे (Bharat Atta) भी बेचने की शुरुआत कर चुकी है। यूं तो अभी भारत ब्रांड चावल (Bharat Brand Rice) की कीमत तय नहीं हुई है, लेकिन बताया जाता है कि इसका दाम 25 रुपये किलो हो सकता है। इसे सरकारी दुकानों से बेचने की तैयारी है।

25 रुपये प्रति किलो चावल

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मध्यमवर्गीय को महंगे चावल से राहत दिलाने के लिए भारत ब्रांड चावल बेचने की तैयारी है। इसी तरह से पहले से भारत

ब्रांड दाल और आटे की बिक्री की जा रही है। भारत ब्रांड चावल बेचने की जिम्मेदारी नेफेड और एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार जैसे संगठनों को दी जाएगी। कोशिश की जा रही है कि इस चावल को पैक कर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों यानी राशन डीलरों के जरिये भी बिकवायी जाए।

बढ़ रही है चावल की कीमत

बीते कुछ समय से चावल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस साल चावल की कीमतों में 14.1 फीसदी तक की तेजी देखने को मिली है। नॉर्मल नॉन ब्रांडेड चावल की कीमत औसत रूप से 43.3 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। ऐसे में चावल के दामों में आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने भारत ब्रांड के तहत सस्ता चावल बेचने का फैसला किया।

पहले से बिक रहा भारत ब्रांड दाल और आटा

महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पहले भारत ब्रांड के तहत सस्ता आटा, दाल, सस्ते प्याज-टमाटर बेचे हैं। 6 नवंबर 2023 को केंद्र सरकार भारत आटा लॉन्च किया था, जिसमें लोगों को 27.50 रुपए प्रति किलो के दर से सस्ता आटा मिल रहा है। इस समय पंसारी की दुकानों में आटे की औसत कीमत 35 रुपए किलो है। इसी तरह से सरकार 60 रुपये प्रति किलो के भाव से भारत दाल बेच रही है। इससे पहले जब प्याज और टमाटर की कीमत सातवें आसमान पर पहुंच गई थी, सरकार ने लोगों को बाजार से कम कीमत पर प्याज-टमाटर मुहैया कराया। गौरतलब है कि नवंबर में खाने-पीने की महंगाई दर 8.70% पर पहुंच गई। वहीं रिटेल महंगाई दर 5.55% पर पहुंच गई है।

एफसीआई से मिलेगा सस्ते चावल

एनसीसीएफ (NCCF) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) से सस्ते चावल की सप्लाई होगी। इसकी छोटी पैकिंग करा के चावल को रिटेल स्टोर या राशन डीलरों के जरिए बेचा जा सकता है। छोटी पैकिंग कितने किलो की होगी, इस सवाल पर उन्होंने बताया कि अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। हो सकता है कि चावल की पैकिंग पांच किलो की हो या 10 किलो की हो। सरकार की तरफ से निर्देश आएगा तो इसकी पैकिंग एक किलो या दो किलो में भी हो सकती है।

मां पार्वती के श्राप ने समुद्र के पानी को किया खारा, आखिरी क्यों हो गईं थीं क्रोधित

पुराणों में लिखी हुई कई कहानियां आज भी रहस्यमयी हैं, लेकिन इनके प्रभाव से कलयुग में भी लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य की गाथा शिव पुराण में भी लिखी हुई है। माता पार्वती ने समुद्र को क्रोधित होकर श्राप दे दिया था, जिसका प्रभाव आज भी दिखता है।

समुद्र को माता पार्वती ने क्यों और क्या श्राप दिया था?

पौराधिक कथा की मानें तो शिव जी को पाने के लिए माता पार्वती ने तप शुरू कर दिया था। वह लगातार 12 सहस्त्र वर्षों तक तप कर रही थीं। उनके तप का तेज देखकर देवलोक में बैठे देवता भी असहज हो गए थे। सभी लोक थर-थर कांपने लगे थे। देवताओं का सिंहासन उनके तप के कारण जब डोलने लगा तो वह भी परेशान हो गए। उनके मन में माता पार्वती के तप को रोकने का विचार करने लगे। वह माता पार्वती के समक्ष विनती करने के लिए पहुंचे। इस बीच समुद्र देव माता पार्वती का तेज देखकर मोहित हो गए।

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

माता पार्वती ने अपना तप पूरा कर आंखे खोलीं तो समुद्र देव ने उनको विवाह का प्रस्ताव दिया। माता पार्वती ने बेहद सहज होकर उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वह शिवजी को ही अपने पति के रूप में मान चुकी हैं। वह किसी ओर के बारे में सोच भी नहीं सकती हूं। यह सुन समुद्र देव क्रोधित हो गए।

समुद्र देव ने घमंड में की गलती

समुद्र देव ने क्रोध में आकर भूल कर दी। उन्होंने भगवान शिव के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। वह घमंड में बोले कि उनका मीठा पानी पी कर ही दुनिया भर के जीवों की प्यास बुझती है। उनका आचरण माता पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।

समुद्र देव ने मांगी क्षमा

माता पार्वती ने समुद्र श्राप दे दिया कि अभी से तुम्हारा पानी खारा हो जाएगा। तुम्हारे पानी को अब से कोई भी नहीं पी पाएगा। माता का श्राप सुनकर समुद्र देव भी परेशान हो गए। उन्होंने बिना देरी किए माता से क्षमा मांगी। माता ने उन्हें क्षमा भी किया, लेकिन श्राप आज तक है।

सोमवार से होगी नए साल की शुरुआत

शिव जी को इन उपाय से कर सकते हैं प्रसन्न

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ इंदौर (म.प्र.)

साल 2024 की शुरुआत खास होने वाली है। नए साल का पहला दिन सोमवार का है। ऐसे में भगवान शिव के दिन आप ज्योतिषीय उपाय कर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। नए साल की शुरुआत में भगवान शिव का आशीर्वाद आपके पूरे साल के लिए शुभ होगा। ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स से आइये जानते हैं इन उपायों के बारे में।

साल 2024 के ज्योतिष उपाय

2024 की शुरुआत सोमवार से हो रही है। ऐसे में यह साल विशेष हो जाता है। आप भगवान शिव पर जल चढ़ाकर नए साल की शुरुआत कर सकते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं। वह बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं।

1 जनवरी 2024 के दिन जलाभिषेक का शुभ समय सुबह 6 बजकर 33 मिनट से लेकर 7 बजकर 56 मिनट तक का है। ऐसे में सही समय पर भगवान शिव को जल चढ़ा देना चाहिए। इस दौरान भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाना न भूलें।

भगवान शिव को बेलपत्र पसंद है। ऐसे में बेलपत्र को भगवान शिव पर चढ़ाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। आपके जीवन में आनने वाली सभी मुश्किलसें हल होंगी। शिव जी सफेद रंग की कोई वस्तु भी चढ़ा सकते हैं।

नए साल की शुरुआत दान से करनी चाहिए। ऐसे में आप दही, सफेद वस्त्र, शक्कर और दूध भी बांट सकते हैं। सर्दी के समय में गरीब लोगों को ठंड से बचाने के लिए सफेद रंग के गर्म वस्त्र भी दान कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्रों इस दिन जाप करना चाहिए। शिव चालीसा का 108 बार लगातार पाठ करने से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलेगी।

नए साल पर इन जानवरों की न लगाएं तस्वीर, घर में हो सकती है क्लेश

नए साल की सजावट का दौर घरों में शुरू हो चुका है। कुछ लोगों को जानवरों की तस्वीरों से घर को सजाने का शौक होता है। ऐसे में यह पता होना बहुत जरूरी है कि किस जानवर की तस्वीर को घर में नहीं लगा सकते हैं। आज इस खबर में हम आपको बताएंगे कि वास्तु के हिसाब से कौन से जानवर की तस्वीर घर पर नहीं लगा सकते हैं।

घर में न लगाएं इन जानवरों की तस्वीर

वास्तु के हिसाब से घर में हिंसक जंगली जानवरों की तस्वीर लगाना अशुभ होता है। घर में कभी भी भूलकर शेर, चीता, भालू आदि की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। लोग कार के पीछे भी सजावट के तौर पर भालू आदि की तस्वीर लगा लेते हैं। यह नहीं करना चाहिए। इन तस्वीरों की वजह से आपके घर का माहौल नकारात्मक हो सकता है। यह घर में परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई-झगड़े का कारण बन सकता है।

घर में हिंसक जानवरों की तस्वीर लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच में रिश्ते खराब हो सकते हैं। यह घर पर पड़ने वाली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऐसे में परिवार के सदस्यों के बीच में ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। लोगों का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, जिससे तरक्की के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। घर की सुख शांति खत्म हो जाती है।

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

नए साल पर काले घोड़े की नाल का करें उपाय, होगा आर्थिक लाभ

आचार्य पं. संजय वर्मा
9826380407
ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ, इंदौर (म.प्र.)

अब कुछ ही दिनों नया साल आने वाला है। नया साल आने से आपके ग्रहों की दिशा भी बदल जाती है, जिससे शुभ और अशुभ दोनों तरह प्रभाव जीवन पर पड़ते हैं। वास्तु शास्त्र में भी कुछ नियम हैं, जिनसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किया जा सकता है। आप काले घोड़े की नाल का उपाय कर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। यह आपके घर को वास्तु दोष से मुक्त करेगा।

रोग दोष से छुटकारा पाने के लिए उपाय

आपके घर का कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, तो आप घोड़े की नाल का उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले घोड़े की नाल की 4 कील बना दें, सवा किलो उड़द की दाल, एक सूखा नारियल रख लें। इसको बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार दें। फिर इसको बहते हुई किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। यह इस उपाय को करने के बाद पीड़ित व्यक्ति ठीक हो जाएगा।

इस दिशा में लगाएं घोड़े की नाल

वास्तु शास्त्र के अनुसार ही घोड़े की नाल को लगाएं। यह घर के उत्तर या पूर्व दिशा में शुभ रहेगा। घर में घोड़े की नाल लगाने से सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी। घर में परिवार के सदस्य सुख-शांति के साथ रहेंगे।

आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए उपाय

आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो उसके लिए घोड़े की नाल का एक उपाय असरदार हो सकता है। आप काले घोड़े के दाहिन पैर की नाल को निकालें। उसके बाद उसको घर की मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसा करने भर से आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी।

29 दिसंबर को कार्य सिद्ध के लिए सबसे शुभ योग, इस मुहूर्त में खरीदारी और दान से मिलेगा 100 गुना फल

गुरु पुष्य योग की सनातन धर्म में विशेष अहमियत है। 29 दिसंबर 2023 को गुरु पुष्य योग बन रहा है। सभी योगों में इस योग को बहुत शुभकर माना जाता है। यह योग कार्यों को सिद्ध करने वाला है। इस दिन गुरु पुष्य के साथ इंद्र, अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि बन रही है। इसलिए विशेष चीजें खरीदना मंगलकारी होता है। आइए जानते हैं गुरु पुष्य योग में क्या खरीदारी करें। 29 दिसंबर को कार्य सिद्ध के लिए सबसे शुभ योग, इस मुहूर्त में खरीदारी और दान से मिलेगा 100 गुना फल29 दिसंबर को कार्य सिद्ध के लिए सबसे शुभ योग, इस मुहूर्त में खरीदारी और दान से मिलेगा 100 गुना फल

गुरु पुष्य योग 2023 शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, गुरु पुष्य नक्षत्र 29 दिसंबर को दोपहर 1.05 बजे से शुरू होगा। यह 30 दिसंबर को दोपहर 3.10 बजे समाप्त होगा। मान्यताओं के अनुसार, माता लक्ष्मी का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था। इस योग में शुभ काम, निवेश और खरीदारी का विशेष महत्व है।

गुरु पुष्य योग में ये चीजें खरीदें

गुरु पुष्य नक्षत्र तिथि पर सोना, पीतल या दक्षिणावर्ती शंख खरीदें। इस दिन गुड़, चना और घी का दान करना शुभ माना जाता है।

PF खाते से अब नहीं निकाल सकेंगे कोरोना एडवांस, ईपीएफओ ने बंद कर दी सुविधा

नई दिल्ली। एजेंसी

ईपीएफओ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए जरूरी खबर है। रिटायरमेंट फंड संस्था ने कोविड एडवांस फैसलिटी को बंद कर दिया है। कोरोना महामारी के समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने खाताधारकों अपने पीएफ अकाउंट में से एडवांस के रूप में पैसे निकालने की सुविधा दी थी। लेकिन अब इस सुविधा को खत्म कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सात महीने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि कोविड-19 महामारी अब पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी नहीं रह गई है। ईपीएफओ के एक अधिकारी ने कहा कि एक हफ्ते पहले अधिकारियों के साथ हुई एक मीटिंग में यह फैसला लिया गया था।

अधिकारी ने कहा, 'अभी इस बारे में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। सॉफ्टवेयर में नॉन-रिफंडेबल कोविड एडवांस के प्रॉविजन को डिसएबल करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सब्सक्राइबर्स इसके लिए आवेदन न कर सकें।' जानकारों का कहना है कि ईपीएफओ के इस कदम में खपत के प्रभावित होने की आशंका है क्योंकि कोविड एडवांस को गैर-जरूरी खर्च के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना है कि ईपीएफओ ने यह फैसला काफी देर से लिया है और इससे ईपीएफओ के पास फंड की उपलब्धता प्रभावित हुई है।

देर से लिया फैसला

लेबर इकनॉमिस्ट केआर श्याम ने कहा कि ईपीएफओ की इस फैसिलिटी ने देश में खपत को बढ़ावा दिया लेकिन इसे लंबे समय तक जारी रखना सही नहीं था। इससे ईपीएफओ के लिए फंड की सप्लाई प्रभावित हुई है जिसे निवेश किया जा सकता था। यानी अप्रत्यक्ष रूप से ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स का रिटर्न प्रभावित हुआ है। ट्रेड यूनियन से जुड़े एक लीडर ने कहा कि यह सरकारी बाबुओं की तरफ से लापरवाही को दिखाता है। उन्होंने कहा, 'यह फैसला काफी देर से लिया गया जबकि सब जानते थे कि इसका इस्तेमाल इलाज के लिए नहीं हो रहा है। इससे सब्सक्राइबर्स की सेविंग कम हो गई है।'

कुल 2.2 करोड़ सब्सक्राइबर्स ने कोरोना एडवांस सुविधा का लाभ उठाया जो ईपीएफओ के कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई से ज्यादा है। यह सुविधा 2020-21 में शुरू हुई थी और तीन साल तक रही। इस दौरान पीएफ सब्सक्राइबर्स ने कोरोना एडवांस के रूप में 48,075.75 करोड़ रुपये निकाले। ईपीएफओ की ड्राफ्ट एन्युअल रिपोर्ट 2022-23 में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ ने 2020-21 में 17,106.17 करोड़ रुपये वितरित किए जिससे 69.2 लाख सब्सक्राइबर्स को फायदा हुआ। साल 2021-22 में 91.6 लाख सब्सक्राइबर्स ने इस सुविधा का लाभ उठाया और 19,126.29 लाख करोड़ रुपये निकाले।

कब-कब कितना पैसा निकाला

इसी तरह 2022-23 में 62 लाख सब्सक्राइबर्स ने अपने पीएफ अकाउंट्स से 11,843.23 करोड़ रुपये की निकासी की। सरकार ने इस सुविधा के लिए मार्च, 2020 में ईपीएफ स्कीम, 1952 के नियमों में संशोधन किया था। यह सुविधा 28 मार्च, 2020 को शुरू की गई थी और पहले चार दिन में यानी 31 मार्च, 2020 तक 33 लोगों ने इसका फायदा उठाया। ईपीएफओ के छह करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और यह 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फंड मैनेज करता है। नौकरीपेशा लोगों के पीएफ खाते में उनकी सैलरी में से हर महीने एक निश्चित अमाउंट काटकर जमा किया जाता है। इस पैसे पर सालाना ब्याज भी मिलता है।

यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने रूस के साथ किया ये अहम परमाणु ऊर्जा समझौता

मास्को। एजेंसी

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय यात्रा पर मास्को में हैं। इस दौरान भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ है। इससे चीन से लेकर अमेरिका तक खलबली मच गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से संबंधित "कुछ बहुत महत्वपूर्ण" समझौतों पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए। जयशंकर रूस के नेतृत्व के साथ बैठक करने के लिए पांच दिवसीय यात्रा पर यहां आए हैं। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ "व्यापक और रचनात्मक" बैठक के बाद यह घोषणा की।

इस बैठक के दौरान परमाणु ऊर्जा और औषधि, फार्मास्युटिकल पदार्थ और चिकित्सीय उपकरणों पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने यहां भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, "आज, मेरी और उप प्रधानमंत्री मंतुरोव की मौजूदगी में, हमने कुडनकुलम परमाणु परियोजना की भविष्य की इकाइयों से जुड़े कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।" रूस की सरकारी मीडिया के अनुसार, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण मार्च 2002 में शुरू हुआ था। फरवरी 2016 के बाद से कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली ऊर्जा इकाई लगातार काम कर रही है, इसकी डिजाइन क्षमता 1,000 मेगावाट की है। संयंत्र के 2027 में पूरी क्षमता के साथ काम शुरू करने की उम्मीद है।

चीन से अमेरिका तक मची खलबली

भारत-रूस के बीच भुगतान समंबंधी दिक्कतें होंगी दूर

बैठक के दौरान जयशंकर ने व्यापार, वित्त, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और परमाणु क्षेत्रों में प्रगति का उल्लेख किया। भारतीय समुदाय को दिए संबोधन में उन्होंने रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे कुछ क्षेत्रों में रूस को "विशेष भागीदार" बताया। उन्होंने कहा, "रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु (ऊर्जा) के क्षेत्रों में उन देशों के साथ सहयोग किया जाता है, जिनके साथ आपका उच्च स्तर का भरोसा है।" जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारत और यूरेशियन आर्थिक क्षेत्र के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर व्यक्तिगत बातचीत शुरू करने के लिए उनकी वार्ता टीम जनवरी के अंत तक मिलेंगी।

उन्होंने कार्यक्रमों में सवालों पर कहा, "आज, जब मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो हम इस पर सहमत हुए कि अगले साल की शुरुआत में हमारे वार्ताकार दल मुलाकात करेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जनवरी के अंत तक आमने-सामने बैठकर बातचीत शुरू करेंगे।" रूस और भारत के बीच भुगतान की समस्या पर एक सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा कि किसी असामान्य स्थिति में हम ऐसे तरीके तलाश कर रहे हैं जिससे बैंक एक-दूसरे के साथ लेनदेन कर सकें।

आज इन नेताओं के साथ है मुलाकात

जयशंकर बुधवार को अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने भारत और रूस के बीच मजबूत और स्थिर भागीदारी का निर्माण करने में भारतीय समुदाय के योगदान की भी प्रशंसा की। जयशंकर ने मंतुरोव के साथ रूसी उद्योग एवं व्यापार प्रदर्शनी का भी दौरा किया। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बावजूद भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत बने रहे हैं। भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल का आयात काफी बढ़ गया है, जबकि कई पश्चिमी देशों में इसे लेकर बेचैनी है। भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की है और वह कहता रहा है कि इस मुद्दे का समाधान कूटनीति और संवाद से किया जाना चाहिए।

कोका-कोला ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के साथ अपनी साझेदारी को आठ वर्षों के लिये बढ़ाया

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) और कोका-कोला ने आठ साल के लिये अपनी वैश्विक भागीदारी की घोषणा की है। इस भागीदारी में 2031 के अंत तक तीनों फॉर्मेट्स में आईसीसी के वर्ल्ड इवेंट्स शामिल होंगे। आईसीसी के मुख्यालय में हुआ आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह इस भागीदारी के लिये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह खेलों के लिये कोका-कोला की प्रतिबद्धता दिखाता है। आईसीसी के ग्लोबल पार्टनर के तौर पर आठ साल की यह भागीदारी किसी एक ब्राण्ड के साथ आईसीसी द्वारा की गई सबसे लंबी भागीदारियों में से एक है। इस प्रकार भागीदारी का कुल समय 13 वर्ष (2019-2031) हो जाता है। इस रिश्ते में कोका-कोला कंपनी के ब्राण्ड्स एक्सक्लूसिव नॉन-अल्कोहॉलिक बेवरेज पार्टनर्स बनेंगे। एग्रीमेंट में खेलों के शिखर पर सारे मेन्स और वूमन्स इवेंट्स शामिल हैं, जैसे कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप्स और आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफीज़, जोकि 2031 के अंत तक चलेंगे। इस भागीदारी के दौरान हर साल बड़े अंतर्राष्ट्रीय मेन्स और वूमन्स इवेंट होंगे और हर दो साल में एक वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल होगा। आईसीसी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर अनुराग दहिया ने कहा: "मैं आईसीसी के ग्लोबल पार्टनर के तौर पर एक बार फिर कोका-कोला कंपनी का स्वागत करते हुए उत्साहित हूँ। हमने आठ साल की एक महत्वपूर्ण भागीदारी की है। यह भागीदारी दुनिया के अग्रणी ब्राण्ड्स को दूसरे सबसे बड़े खेल से जोड़ती है। लंबे समय के लिये हुआ यह गठजोड़ एक नये वाणिज्यिक युग की शुरूआत करता है, जोकि इस खेल के लिये रोमांचक संभावनाओं से भरा है। यूएसए और वेस्ट इंडीज में मेन्स टी20 वर्ल्ड कप और बांग्लादेश में वूमन्स एडिशन होने ही वाला है, जिसे देखते हुए हम दुनिया में शानदार तरक्की और जुड़ाव की स्थिति में हैं। इस भागीदारी से न सिर्फ हमारे खेल का विस्तार करने की खुशी मिलेगी, बल्कि हमें दुनियाभर में हमारे प्रशंसकों के अनुभव को बेहतर बनाने के खोजपरक मौके भी मिलेंगे।"

बैंकों में जमा 42270 करोड़ रुपये का नहीं है कोई दावेदार

क्या होता है इन पैसों का

नई दिल्ली। एजेंसी

बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते साल के मुकाबले इस साल अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की रकम 28 फीसदी तक बढ़ गई है। बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स यानि बिना दावे वाली रकम बढ़कर 42270 करोड़ रुपये पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2023 तक बैंकों में बिना दावे वाली रकम बढ़कर 42,270 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो मार्च 2022 तक 32,934 करोड़ रुपये था। बैंकों में जमा इन पैसों का काई दावेदार नहीं है। 42,270 करोड़ की अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स में से सरकारी बैंकों के पास 36185 करोड़ रुपये

और प्राइवेट बैंकों में 6087 करोड़ रुपये जमा है। आपको बता दें कि बैंकों में जमा पैसों पर अगर कोई 10 साल या उससे अधिक वर्षों तक कोई दावा नहीं करता है तो बिना दावे वाली रकम मान लिया जाता है। बिना दावे वाली इन राशि को बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डीईए फंड में भेज देते हैं। वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने इस बारे में राज्यसभा में जानकारी दी और बताया कि मार्च 2021 तक सरकारी बैंकों में जहां 23683 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स में थे तो वहीं प्राइवेट बैंकों में 4141 करोड़। मार्च 2022 में यह रकम बढ़कर सरकारी बैंकों में 27921 करोड़ रुपये औ निजी बैंकों में 5013 करोड़ हो गए। मार्च 2023 तक इसमें 28 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई। उन्होंने बताया कि आरबीआई ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स में कमी लाने के लिए आरबीआई लगातार कदम उठा रही है। सही व्यक्ति की पहचान कर उनका पैसा लौटाया जा सके इसके लिए आरबीआई की ओर से कोशिश जारी है।

एमेजॉन इंडिया ने पूर्व-सैनिकों को नौकरी के अवसर देने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

एमेजॉन इंडिया ने पूर्व-सैनिकों को कंपनी में नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय तट रक्षक (घ्उ) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो कंपनी में एक समावेशी कार्यस्थल बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। एमेजॉन इंडिया में काम करने वाले लोगों में विविधता, समानता और समावेशन पर निरंतर ध्यान दिया जाता है, ताकि अलग-अलग लोगों के दृष्टिकोण को महत्व व सम्मान मिल सके। कंपनी एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देती है जो विकास के लिए अनुकूल हो और लोगों को अपनी पूरी क्षमता के साथ सबसे बेहतर काम करने में समर्थ बनाए। पिछले कुछ सालों में एमेजॉन इंडिया ने अपने कार्यबल में विविधता, समानता और समावेशन लाने के लिए कई पहल शुरू की हैं।

एमेजॉन इंडिया ने अगस्त 2019 में भारत में अपने के फुलफ़िलमेंट नेटवर्क में पूर्व सैनिकों और उनके जीवनसाथियों को सैकड़ों अवसर देने के लिए मिलिट्री वेटरन रोजगार कार्यक्रम शुरू किया। यह प्रोग्राम भारत में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए नौकरी के

अवसर उत्पन्न करने के लिए आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन (AWPO) के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था। एमेजॉन इंडिया ने हाल ही में डायरेक्टोरेट जनरल रिसेटलमेंट (DGR) के साथ अपने समझौता ज्ञापन (MOU) को आगे बढ़ाकर भारत में अपने बढ़ते ऑपरेशंस नेटवर्क में पूर्व-सैनिकों को नौकरी के अवसर देने की प्रतिबद्धता को और ज़्यादा मजबूत किया है। डीजीआर के साथ इस समझौता ज्ञापन से एमेजॉन इंडिया को पूर्व-सैनिकों की प्रतिभा का उपयोग अपनी कंपनी के लिए करने का अवसर मिलता है।

दीप्ति वर्मा, वीपी, पीपल एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी, एमेजॉन इंडिया, जापान एवं उभरते बाजार ने कहा, 'एमेजॉन में हम अपने कार्यस्थल में विविधता, समानता और समावेशन मजबूत बनाने के अपने प्रयास आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रसन्न हैं। पूर्व-सैनिकों के विस्तृत अनुभव और अद्वितीय दृष्टिकोण की गहरी सराहना के कारण एमेजॉन पूरे विश्व में मिलिट्री वेटरन रोज़गार कार्यक्रम चलाता है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद अब हम अपने पूर्व-सैनिकों और उनके परिवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के साझा उद्देश्य के लिए भारतीय तटरक्षक बल के साथ काम करेंगे। हम पूर्व-सैनिकों के समृद्ध अनुभव से लाभान्वित होते रहेंगे, जो एमेजॉन को अपना बहुमूल्य योगदान देंगे।' भारतीय तटरक्षक बल ने कहा, 'विभिन्न उद्योग और व्यवसाय सफलता की ओर बढ़ने के लिए हमारे पूर्व-सैनिकों के विस्तृत अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। एमेजॉन इंडिया ने पूर्व-सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। यह समझौता ज्ञापन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम दोनों का उद्देश्य एक हैः भारतीय तटरक्षक बल के पूर्व-सैनिकों के लिए उपयोगी करियर का निर्माण करना।'

अब मध्य प्रदेश के हर जिले में उपलब्ध हो सकेंगी गृहम हाउसिंग फाइनेंस (जीएचएफएल) की सेवाएँ

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

हाल ही में अपनी रीब्रांडिंग एक्सरसाइज के बाद पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जाने वाली गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जीएचएफएल) अपने प्रमुख बाजारों में से एक, मध्य प्रदेश में और अधिक विकास का लक्ष्य साध रहा है। भारत भर के 19 राज्यों में मौजूद, जीएचएफएल की एमपी में 31 शाखाएं हैं जो कुल मिलाकर 15000 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती हैं। उनमें से लगभग 7000 एश्ध्-एए श्रेणी (सेल्फ मेड इन्डिविजुअल और सेल्फ- कंस्ट्रक्शन) से संबंधित हैं, जो जीएचएफएल के होम लोन कस्टमर का बड़ा हिस्सा है। पिछले 6 वर्षों में एनुअल डिस्बर्सल 36 करोड़ रुपये से बढ़कर अनुमानित 600 करोड़ रुपये और कुल मिलाकर 1500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इससे जीएचएफएल के कुल डिस्बर्सल में एमपी का योगदान वित्त वर्ष 2018 में 6% से बढ़कर वर्तमान में ।20% से अधिक हो गया है।

GRIHUM
HOUSING FINANCE
Apna Ghar. Apni Pehchan.

स्व-निर्मित परियोजनाएं पूरे लोकल कंस्ट्रक्शन इकोसिस्टम को लाभ पहुंचाती हैं, क्योंकि उनमें निर्माण श्रमिक, मिस्त्री, राजमिस्त्री, बढ़ई, प्लंबर, पेंटर शामिल होते हैं, जिससे उन्हें रोजगार और आय सहायता मिलती है। कई बार ग्राहक भी इसी इकोसिस्टम से आते हैं. इसलिए स्व-निर्माण 'वास्तविक भारत' पर काफी ज्यादा आर्थिक जीर्णोद्धार करता है।

SVAMITVA (सर्वे ऑफ़ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया) जैसे सरकारी मिशनों में योगदान देना, यह अर्ध-शहरी भारत में गृह स्वामित्व को अधिक सक्षम करने के लिए जीएचएफएल की प्रेरणा है। SVAMITVA ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण भारत के लिए इंटरग्रेटेड प्रॉपर्टी वेलिडेशन सॉल्यूशन देने की एक विधि है। इससे देशभर के गांवों में लाखों ग्रामीण भूमि के मालिकों को फायदा होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के लिए कंपनी की योजनाओं पर बोलते हुए, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री मनीष जयसवाल ने कहा, 'हमारे अधिकांश ग्राहक स्व-निर्मित व्यक्ति हैं जिनके लिए घर खरीदना सबसे बड़ी आकांक्षा है। उनकी सीमित शिक्षा और अनुभव को देखते हुए, उन्हें गृह ऋण प्रक्रिया में सहयोग की आवश्यकता है - गृहम' हमारे ग्राहकों के लिए 'ड्रीम होम' बनाने में सहयोग और एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। मध्य प्रदेश हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हम राज्य के 31 शहरों में मौजूद हैं और 15000 स्व-निर्मित व्यक्तियों को सशक्त बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य राज्य के हर जिले तक पहुंचना है।'

5 महीने के निचले स्तर पर भारतीय करेंसी

आज डॉलर के मुकाबले इतने पैसे गिरा रुपया

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

लागातर डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी में गिरावट दर्ज हुई है। यह गिरावट डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने और Read Sea Route (लाल सागर) माध्यम से वैश्विक व्यापारी में व्यवधान ने भी भारतीय करेंसी पर असर डाला है। वहीं आज शेयर मार्केट रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ है। आज सेंसेक्स पहली बार 72000 अंक के पार पहुंच कर बंद हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ है। विदेशी फंडों के निरंतर बहिर्वाह और वैश्विक बाजार में हो रहे आउटफ्लो ने भारतीय करेंसी को सीमित दायरे में डाल दिया है। वैश्विक बाजार में डॉलर की बढ़ती मांग की वजह से आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे गिरकर 83.35 (अनंतिम) पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों के अनुसार शेयर मार्केट में मजबूत खरीदारी का रुझान भारतीय करेंसी को बढ़ावा देने में विफल रहा क्योंकि निवेशक लाल सागर मार्ग (Read Sea Route) के माध्यम से वैश्विक व्यापार में व्यवधान के डर से कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों को लेकर चिंतित रहे। निचले स्तर पर रुपया इंटरबैंक विदेशी मुद्रा में, घरेलू मुद्रा 83.21 पर खुली और इंट्रा-डे सौदों के दौरान डॉलर के मुकाबले 83.20 के शिखर और 83.35 के निम्नतम स्तर के बीच कारोबार किया। भारतीय करेंसी अंततः ग्रीनबैक के मुकाबले 83.35 (अनंतिम) पर बंद हुई, जो पिछले बंद से 16 पैसे की गिरावट दर्ज करती है। बीते दिन मंगलवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 83.19 पर बंद हुई।

मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए 24 घंटे भर्ती रहना जरूरी?

अब क्या करने जा रही है सरकार

नई दिल्ली। एजेंसी

इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होने पर इंश्योरेंस कंपनियां मेडिकल क्लेम का भुगतान करने से इन्कार कर देती हैं। लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में हुई तरक्की के बाद अब सर्जरी या इलाज कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है तो फिर इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए 24 घंटे भर्ती रहना जरूरी है? उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का कहना है कि वह इस बारे में इंश्योरेंस रेगुलेटर ध्ध्ध् और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) से बात करेगा।

नेशनल कंज्यूमर कमीशन के चीफ ने रविवार को यह मुद्दा उठाया। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे पर आयोजित एक कार्यक्रम में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रसल कमीशन (NCDRC) के चेयरमैन जस्टिस अमरेश्वर प्रसाद साही ने कहा कि अगर कोई मरीज कम से कम 24 घंटे के लिए एडमिट नहीं होता है तो इसका मेडिकल क्लेम स्वीकार नहीं किया जाता है। मेडिकल क्लेम और मेडिकल नेग्लिजेंस के मामलों में अक्सर ऐसा देखने में आता है। कुछ जिला फोरम ने 23.5 घंटे में भी क्लेम देने का ऑर्डर दिया है। उनका तर्क है कि अब कई तरह की सर्जरी में 24 घंटे से भी कम समय लगता है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनियों को इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है।

नहीं है जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर

जस्टिस साही ने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम के मामले में पंजाब और केरल के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशंस ने ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। अगस्त में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने एक ऐसा ही फैसला दिया था। इंश्योरेंस कंपनी ने 24 घंटे से कम भर्ती रहने पर क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। इस पर कमीशन ने कंपनी को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार करार दिया था। एनसीडीआरसी के चीफ ने कहा कि शिकायतों को जल्दी से जल्दी निपटाया जा रहा है लेकिन कमीशन को अपने आदेश लागू करवाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'हमें आदेश लागू करने वाले लिए सिविल कोर्ट की ही तरह शक्तियां मिली हैं लेकिन इसके लिए हमारे पास जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर इस बारे में कोई स्टैंडर्डाइज स्कीम निकाली जाती है तो इससे कंज्यूमर जस्टिस को बल मिलेगा।'

इस बीच यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमान ने टीओआई से कहा कि उपभोक्ताओं के हित में हम यह मुद्दा आईआरडीए और डीएफएस के सामने उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी डॉक्युमेंटेशन और प्रोसेसेज को आसान बनाने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर के साथ बात की थी। हमारा फोकस समाधान खोजने और विवादों को कम करने पर है। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी ने जिला और राज्य स्तर पर कंज्यूमर कमीशंस के प्रयासों की सराहना की। इस साल उन्होंने 1.77 लाख शिकायतों का निपटारा किया जबकि 1.61 लाख नए केस दाखिल हुए। इसी तरह एनसीडीआरसी ने इस साल 200 परसेंट मामलों का निपटारा किया।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।